तिब्बत देश

तिब्बत में खनिजों की उपनिवेशवादी लूट

कभी–कभी ऐसा लगता है कि तिब्बत में चीन के उपनिवेशवादी नियंत्रण का सवाल एक पिटी–पिटाई लकीर पर चलने के लिए अभिशापित हो चुका है। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन और सरकारें तिब्बती जनता के राजनीतिक दमन, मानवाधिकारों के हनन और सांस्कृतिक विनाश जैसे विषयों पर अपनी चिंता जताकर अपनी जिम्मेदारी पूरी हुई मान लेती हैं। जवाब में चीन सरकार भी तिब्बत को 'चीन का अविभाज्य अंग' बताकर वहां सड़कों का जाल बिछाने, अरबों डालर की कीमत पर तिब्बत में रेलगाड़ी ले जाने और तिब्बती शहरों–कस्बों में आधुनिक निर्माण जैसे कई उदाहरण देकर यह सिद्ध करने की कोशिश करती है कि 1951 में तिब्बत के चीन में 'शामिल' होने के बाद तिब्बत में भारी 'विकास' हुआ है। चीनी नेता दावा करते हैं कि इस काम में चीन की भूमिका चीनी जनता की कीमत पर तिब्बत को 'विकास सहायता' देने से कम नहीं है।

इसमें शक नहीं कि 1951 में तिब्बत पर चीनी कब्जे से पहले आधुनिक विकास के मामले में तिब्बत दुनिया के सबसे अविकसित देशों की सूची में था। इसमें भी शक नहीं कि 1951 के बाद, खासतौर से पिछले 15–20 साल में चीन ने तिब्बत में बहुत विशाल पैमाने पर सड़कों, हवाई अड्डों, रेलवे लाइन और शहरों का निर्माण किया है। लेकिन पिछले 60 साल में तिब्बत का इतिहास यह भी बताता है कि इस सारे 'विकास' कार्य के पीछे चीन का इरादा तिब्बती जनता का कल्याण नहीं बल्कि तिब्बत पर चीन की सैनिक और प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना रहा है।

पहले इस विकास कार्य का लक्ष्य भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान से लगने वाली तिब्बती सीमाओं पर अपनी सैनिक मौजूदगी पक्की करना और इन सैनिक ठिकानों तक चीनी सेना के लिए पक्की सड़कें और हवाई अड्डे बनाना था। अब पूरे तिब्बत में दर्जनों नए शहरों और कस्बों के निर्माण का लक्ष्य चीन से लाकर लाखों की संख्या में स्थायी रूप से बसाए जा रहे चीनी नागरिकों के लिए आधुनिक सुविधाएं जुटाना है। इस अभियान का असली लक्ष्य तिब्बती जनता को अपने ही देश में अर्थहीन अल्पसंसख्यक बनाकर वहां स्थायी चीनी कब्जा सुनिश्चित करना है। ठीक वैसे ही जैसे चीन मंचूरिया और भीतरी मंगोलिया जैसी दर्जनों 'राष्ट्रीयताओं' के साथ कर चुका है और पूर्वी तुर्किस्तान (शिंजियांग) में कर रहा है। ल्हासा और शिगात्से जैसे कई शहरों में वह इस लक्ष्य को हासिल भी कर चुका है। तिब्बत में चीन के इस 'आर्थिक विकास' का एक और पहलू है जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत देरी से समझा जा रहा है। तिब्बत में रेलवे लाइन आ जाने के बाद अचानक ही वहां खनिजों के दोहन से जुड़े उद्योगों का बेतहाशा फैलाव होने लगा है। इससे पहले तिब्बत में केवल यूरेनियम, सोना और तांबे जैसे कुछ खनिजों का दोहन किया जाता था। लेकिन गोरमो से ल्हासा के बीच 1200 किमी लंबा रेलवे संपर्क जुड़ने के बाद अचानक ही भूगर्भ से जुड़े चीनी विभागों और खोज संस्थाओं से इस मार्ग पर कई तरह के खनिज भंडारों की खबरें आने लगी हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस रेलमार्ग से चीन को जोड़ने वाली 72 काऊंटियों में कम से कम 90 खानों पर काम शुरू हो चुका है। पिछले मार्च में चीनी समाचार एजेंसी शिनहुआ ने सरकारी सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि तिब्बत में 3000 से ज्यादा स्थानों पर 102 किस्म के खनिज खोजे जा चुके हैं। इन खानों से अगले कुछ साल में 12 हजार 500 करोड़ अमेरिकी डालर के बराबर खनिज निकलने की उम्मीद की जा रही है। तिब्बती खनिज संपदा से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने आशा व्यक्त की है कि 2020 तक तिब्बत से होने वाली खनिजों की आय मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़कर वहां के कुल सकल उत्पादन का 30 से 50 प्रश हिस्सा हो जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आंकड़े केवल 'तिब्बत ऑटोनॉमस रिजन' (टार) के हैं जो मूल तिब्बत का लगभग एक तिहाई है। तिब्बत के बाकी दो बड़े प्रांतों खम और आम्दो को 1960 वाले दशक में तिब्बत से काटकर आसपास के चीनी प्रांतों में मिला दिया गया था। इन इलाकों को चीन सरकार तिब्बत का हिस्सा नहीं मानती। तिब्बत में चीनी रेल लाने के समर्थन में तत्कालीन प्रधान देंग सिआओ पिंग ने इस महंगी परियोजना की यह कहकर वकालत की थी कि आर्थिक रूप से भले ही यह लाभकारी न हो पर इसका राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है कि देंग के असली इरादे राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तर पर थे।

चीनी उद्योगों में नई टैक्नोलाजी आने के बावजूद वहां खनिजों और खनन की टैक्नोलाजी बहुत अधकचरी है जिसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में खानों से जुड़ी सबसे ज्यादा गंभीर दुर्घटनाएं चीन में होती हैं। यही कारण है कि तिब्बत में इतने विशाल पैमाने पर खनिजों के दोहन से उत्साहित चीन सरकार अब दुनिया भर की खनन कंपनियों को तिब्बत में आमंत्रित कर रही है। तिब्बत की इस औपनिवेशिक लूट का कई देशों में तिब्बत समर्थक विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के चलते आस्ट्रेलिया की रियो टिंटो कंपनी को अपनी तिब्बत योजना रद्द करनी पड़ी थी और आस्ट्रेलिया–चीन सहयोग वाली सिनो–गोल्ड कंपनी को 2003 में पूर्वी तिब्बत की सोने की खान में अपना काम बंद करना पड़ा था। लेकिन कनाडा की कम से कम छह कंपनियां जनविरोध के बावजूद तिब्बत में खनन करने की दिशा में जुटी हुई हैं। तिब्बत में ये कंपनियां चीन की सरकारी कंपनियों की जूनियर भागीदार के रूप में काम कर रही हैं।

तिब्बत से खनिजों की इस उपनिवेशी लूट से चीन को भले ही भारी फायदा हो रहा है पर तिब्बत पर इसके बुरे असर अभी से दिखाई देने लगे हैं। खानों के लिए तिब्बती जनता से जबरन जमीन छीने जाने, खानों के कारण जमीन और पानी के प्रदूषण और भारी संख्या में चीनी कर्मचारियों को वहां बसाने के विरोध में तिब्बत में कई आंदोलन हो चुके हैं। खनन में लगी चीनी कंपनियां अक्सर इन प्रदर्शनों को 'तिब्बत की आजादी' के आंदोलन का नाम देकर पुलिस और सेना की मदद से इन्हें कुचल देती हैं।

फिनलैंड के 'साइंस आफ टोटल एनवायरनमेंट' में सितंबर 2010 में छपे एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार तिब्बत के ऐतिहासिक राजा स्रांग्सेन गोंपो के जन्मस्थान ग्यामा में पिछले बीस साल से कम से कम छह खानें चल रही हैं जिसके कारण वहां से आगे ल्हासा नदी और यारलुंग सांग्पो के पानी में तांबे, सीसे, लोहे और अल्मुनियम के जहरीले नमक घुल रहे हैं। इस कारण तिब्बत और चीन के अलावा आगे के कई देशों की जनता के लिए खतरा पैदा हो चुका है। जून 2010 में खान कंपनी के कारण आसपास के कई गांवों में अकाल की हालत हो गई। इसके विरोध में लगभग एक सौ तिब्बतियों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन पर 'तिब्बती आजादी' का ठप्पा लगने से बचाने के लिए प्रदर्शनकारी चीनी झंडे लिए हुए थे। लेकिन फिर भी पुलिस की गोली में तीन तिब्बती मारे गए, 30 धायल हुए और 35 को जेल में डाल दिया गया। कई स्थानों पर खानों के जहरीले पानी के कारण जानवरों के बीमार होने और मरने की खबरें आना आम बात हो चुकी है।

चीनी संस्कृति में किसी राजा के जन्मस्थान पर खनन को पाप माना जाता है। लेकिन तिब्बत के मामले में चीनी कंपनियों का रवैया उनका औपनिवेशिक चरित्र दिखाता है। इस चीनी रवैये का तिब्बत में लगातार विरोध हो रहा है। इसी विरोध को स्वर देते हुए तिब्बत की जानीमानी और मानवाधिकारवादी लेखिका सेरिंग वोज़ेर ने हाल ही में लिखा है, ''चीन सरकार दावा करती है कि तिब्बत में खनन से भारी पूंजी का निर्माण होगा। लेकिन असल में इसकी वजह से तिब्बती जनता को जो लाभ के बजाए कहीं ज्यादा बड़ी हानि हो रही है।''

सवाल उठता है कि क्या दुनिया भर की सरकारें और मानवाधिकार संगठन चीनी दादागीरी के आगे बार–बार झुकते चले जाने की अपनी परंपरा को तोड़ने का साहस दिखाएंगी ?

– विजय क्रान्ति

तिब्बती भिक्षु को तीन साल कारावास की सजा मिली

(टीसीएचआरडी, 20 दिसंबर)

रिपोर्ट में कहा गया था कि मारे गए लोग चीन सरकार की पिछले पांच दशकों से जारी गलत नीतियों के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे।

तिब्बत के गांसू प्रांत के मु–रा मठ के 34 साल के तिब्बती भिक्षु सनग्रैब ग्यात्सो को गत 16 दिसंबर को कानलो माध्यमिक जन न्यायालय द्वारा तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई है।रेवा–कांग–लाम (उम्मीद की यात्रा) पत्रिका के संपादक और 'मातृभाषा बहाल करो संघ' के सदस्य ग्यात्सो पर आरोप है कि उन्होंने मार्च, 2010 में माछू काउंटी में छात्रों द्वारा होने वाले एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अुगवाई की थी। उन्हें पहली बार 17 मार्च, 2008 को भी माछू काउंटी से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही रिहा कर दिया गया था। इसके बाद 18 मार्च, 2008 को उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया और फिर कुछ दिनों के बाद रिहा कर दिया गया। पिछली बार उन्हें 25 मार्च, 2010 को गिरफ्तार किया गया और तब से वह हिरासत में ही हैं।

भारी सजा मिलने के बाद तीन भिक्षुओं को कोई पता नही

(रेडियो फ्री एशिया, 22 दिसंबर)

उन्हें सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वे वरिष्ठ और प्रमुख भिक्षु थे।

चीनी न्यायायल द्वारा भारी सजा सुनाए जाने के बाद से ही तीन बौद्ध भिक्षुओं जामपेल वांगचुक, कोंछोक निमा और गवांग छोनेयी का कोई पता नहीं चल पा रहा है। इन तीनों को क्रमशः आजीवन कारावास, 20 साल कारावास और 15 साल कारावास की सजा सुनाई गई थी।ये तीनों भिक्षु तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में ल्हासा के बाहर स्थित ड्रेपंग मठ से जुड़े थे।10 मार्च, 2008 को मठ द्वारा किए गए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के बाद इन्हें अप्रैल, 2008 को गिरफ्तार किया गया था।जानकारों का कहना है कि तिब्बत में अदालती कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है और न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाता है। वाशिंगटन की संस्था इंटरनेशनल कैम्पेन फॉर टिबेट के अध्यक्ष मैरी बेथ मार्की ने कहा,"हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा कि वे भिक्षु कहां हैं। ड्रेपंग मठ के लोगों का कहना है कि वे किसी भी तरह से चीन की कथित राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं थे, उन्हें सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वे वरिष्ठ और प्रमुख भिक्षु थे।"मार्की ने कहा चीन सरकार भिक्षुओं के मामले को जिस तरह से देख रही है उससे पता चलता है कि तिब्बती इलाकों में आधिकारिक उत्पीड़न का व्यापक चलन है।तिब्बत विशेषज्ञ रोबी बार्नेट ने तिब्बत के अपने सूत्रों के हवाले से इस बात की पुष्टि की है कि जामपेल वांगचुक और कोंछोक निमा को सजा सुनाई गई है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में आधुनिक तिब्बती कार्यक्रम के निदेशक बार्नेट ने कहा कि जून माह में एक अघोषित मुकदमे में इन दोनों को सजा सुना दी गई। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं और ल्हासा के लोगों को भी इस मुकदमे की, उन पर लगे आरोपों की या इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें कहां रखा गया है।

रिपोर्ट से हुआ तिब्बती प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग का खुलासा

(टिबेट डॉट नेट, 1 दिसंबर)

एक नई रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हुई है कि तिब्बत में मार्च 2008 में तिब्बतियों द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर चीनी सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को उन 6 तिब्बतियों की सूची मिली है जो मार्च, 2008 में ल्हासा में हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए थे।ये नाम उस

सूची से मेल खाते हैं जिसमें साल 2008 में तिब्बत से हासिल जानकारी के आधार पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा संकलित मष्तकों के नाम जारी किए गए थे। मार्च, 2008 से ही चीन द्वारा इन प्रदर्शनों के दमन से 227 तिब्बती मारे गए थे जिनमें से 107 लोग अंधाधुंध फायरिंग की वजह से मारे गए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि मारे गए लोग चीन सरकार की पिछले पांच दशकों से जारी गलत नीतियों के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। मार्च के विरोध प्रदर्शनों के बाद चीन सरकार ने मारे गए और घायल तिब्बतियों के बारे में गलत जानकारी दी थी।बीजिंग स्थित चीन सरकार के जनसुरक्षा ब्यूरो द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कथित '3–14 घटना' के बारे में अंतरराष्ट्रीय मीडिया को गलत आंकड़े दिए थे। इसके अलावा चीन ने जानबूझकर चीनी सुरक्षा बलों द्वारा तिब्बती प्रदर्शनकारियों की बर्बर हत्या को ढंकने का प्रयास किया।

चीन से भागकर आने वाले तिब्बतियों को गिरफ्तार करने का नेपाल को मिला ईनाम

(आईबीएन लाइव, 20 दिसंबर)

चीन विरोधी प्रदर्शनकारियों पर अंकुश लगाने के लिए नेपाल सरकार पर भारी दबाव बनाने के लिए चीन सरकार ने तिब्बत से भागकर नेपाल आने वाले तिब्बतियों को पकड़ने वाली नेपाली पुलिस को ईनाम देने के लिए अपने वित्तीय ताकत का इस्तेमाल किया है। विकीलीक्स द्वारा जारी गुप्त अमेरिकी केबल्स से यह बात सामने आई है। विकीलीक्स द्वारा लीक हुए 22 फरवरी, 2010 के केबल से यह पता चलता है कि "चीन सरकार ने उन नेपाली सुरक्षा अधिकारियों को आर्थिक ईनाम दिया है जिन्होंने चीन से भागने की कोशिश कर रहे तिब्बतियों को पकड़ कर चीन को सौंपा है।"पिछले कुछ साल से भारत आने वाले तिब्बतियों की संख्या घटी है क्योंकि नेपाल पर चीन का दबाव बढ़ा है। चीन ने नेपाल सरकार से कहा है कि वह सीमा पर नेपाली सुरक्षा बलों की गश्ती कराए और तिब्बतियों को किसी भी तरह से नेपाल में न घुसने दे। केबल में कहा गया है कि "मार्च 2008 के विद्रोह के बाद भारत आने वाले तिब्बतियों की संख्या घटी है। चीन नेपाल से बार–बार यह कहता रहा है कि वह अपनी सीमा में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों को काबू में रखे और विरोध प्रदर्शनों पर अंकुश लगाए। नेपाल ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और निर्वासित तिब्बतियों को चेतावनी दी है कि वे चीन विरोधी प्रदर्शन न करें।

पिछले महीने ही नेपाल और चीन ने 13 बिंदुओ वाला समझौता किया है जिसका एक बिंदु यह भी था कि सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी ताकि तिब्बती लोग नेपाल में प्रवेश न कर सकें।

तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के चीनी अधिकारियों ने नेपाल का दौरा किया

(फायूल, 23 दिसंबर)

तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र से आए 10 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल ने 22 दिसंबर को काठमांडू में नेपाल के गृह मंत्री भीम रावल से मुलाकात की। टीएआर के उप गवर्नर ली झाओ के नेतृत्व में आए इस प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलकर सीमा सुरक्षा जैसे कई मसलों पर बात की।पिछले महीने ही नेपाल और चीन ने 13बिंदुओ वाला समझौता किया है जिसका एक बिंदु यह भी था कि सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी ताकि तिब्बती लोग नेपाल में प्रवेश न कर सकें।गत 28 नवंबर को दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच तिब्बत की सीमा के नजदीक चौतरा में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई है जिस में यह निर्णय लिया गया है कि, ''नेपाल में तिब्बती नागरिकों के आने पर सख्ती बरती जाए और अस्थायी एंट्री कार्ड के वितरण को व्यवस्थित रूप दिया जाए।चीन ने हाल

चीन सरकार की योजना साल 2020 तक खनन उद्योग का जीडीपी में योगदान 3 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी करना है।

"नेपाल, तिब्बत और पाकिस्तान में चीन की सक्रियता बढ़ रही है।

में नेपाल से कहा है कि तिब्बत से पलायन करने वाले या तिब्बत में घुसने की कोशिश करने वाले तिब्बतियों को रोकने के लिए चीन–नेपाल सीमा पर करीब 10,000 सुरक्षा कर्मियों को लगाया जाए।इसके बदले चीन ने भरोसा दिया है कि वह इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव सहयोग करेगा।

चीन का खनन उपनिवेश बन गया है तिब्बत

"हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा कि वे भिक्षु कहां हैं। ड्रेपंग मठ के लोगों का कहना है कि वे किसी भी तरह से चीन की कथित राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं थे, उन्हें सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वे वरिष्ठ और प्रमुख भिक्षु थे।"

(वैंकुवर मीडिया, 30 दिसंबर)

सीमित बुनियादी ढांचे और निवेश की वजह से साल 2006 में तिब्बत में खोजे गए खदानों के सिर्फ एक फीसदी हिस्से का दोहन हो पाया था। लेकिन क्विंघई–तिब्बत रेलमार्ग की शुरुआत के बाद तिब्बत में खनन अभियान तेज हो गया है।यह रेलमार्ग तिब्बत के सभी 72 काउंटी को चीन से जोड़ता है। अब तिब्बत में करीब 90 खदानों में खनन कार्य चल रहा है और हर काउंटी में कम से कम एक खदान जरूर है। चीन सरकार ने मार्च माह में घोषणा की है कि वह तिब्बत के करीब 3,000 खनिज भंडारों का दोहन कर वहां का विकास करेगी। इन भंडारों में करीब 125 अरब डॉलर के खनिज मिलने की उम्मीद है। चीन सरकार की योजना साल 2020 तक खनन उद्योग का जीडीपी में योगदान 3 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी करना है। तिब्बती लेखक वुएजर ने बताया, "तिब्बत के पर्यावरण और तिब्बती ग्रामीणों, किसानों और घूमंतू जातियों की जीवन शैली को चीन नष्ट कर रहा है। अब वहां कई ऐसे रोग फैल गए हैं जो ग्रामीणों के लिए नए हैं और जिनका उपचार नहीं हो पा रहा।मेमनों और गायों को भी कई तरह के रोग पकड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में उनकी मौत हुई है।"

जिम्मेदारी से बचने के लिए चीन ने बुरी तरह प्रताड़ित भिक्षुओं को रिहा किया

(टिबेटन रीव्यू डॉट नेट, 29 दिसंबर)

तिब्बत के क्विंघई प्रांत के सोलहो प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित मांगरा काउंटी में चीनी अधिकारियों द्वारा जेल में डाले गए चार भिक्षुओं को 24 फरवरी,2011 को सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया गया है। इसकी साफ वजह यह है कि बुरी तरह प्रताड़ित किए गए इन भिक्षुओं के खराब स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अधिकारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। ओस्लो स्थित वायस ऑफ टिबेट रेडियो सर्विस ने 27 दिसंबर को खबर दी है कि लंबे समय से जारी प्रताड़ना और पिटाई की वजह से इन भिक्षुओं के कैद में ही निधन का खतरा दिख रहा था।इन्हें 25 फरवरी,2009 को ही गिरफ्तार किया गया था।ये भिक्षु 23 साल के कालसांग ग्यात्सो, 26 साल के सोएपा ग्यात्सो, 24 साल के लुंगतोक ग्यात्सो और 21 साल के सोएपा ग्यात्सो स्थानीय लुत्सांग मठ के उन 109 भिक्षुओं के समूह में शामिल थे जिन्होंने 25 फरवरी, 2009 को तिब्बती नववर्ष के अवसर पर एक मौन विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इस विरोध यात्रा का अंत काउंटी सरकार के मुख्यालय के सामने मोमबत्तियां जलाकर किया गया था।इसके बाद पास के एक स्कूल में मौजूद सभी भिक्षुओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कई बार चीन की कथित देशभक्ति शिक्षा दी गई। उक्त चारों भिक्षुओं के अलावा बाकी सबको रिहा कर दिया गया।चीनी सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर तिब्बतियों की हत्या के विरोध में भिक्षुओं ने नए साल का उत्सव न मनाने का निर्णय लिया था और यह विरोध प्रदर्शन भी इस बहिष्कार का हिस्सा था।

संयुक्त राष्ट्र ने चीन से कहा, खानाब दोशों पर पशुओं को बेचने और कहीं बसने का दबाव न बनाएं

(आईसीटी, 23 दिसंबर)

चीन में 15 से 23 दिसंबर के अपने 9 दिवसीय दौरे की समाप्ति पर संयुक्त राष्ट्र में खाद्य अधिकार के विशेष दूत ओलिवियर डी शटर ने कहा कि तिब्बती और मंगोलियाई घूमंतू जातियों को कहीं एक जगह बसने को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। 23 दिसंबर को जारी विशेष दूत की रिपोर्ट में कहा गया है, "इस बात में कोई संदेह नहीं कि जमीन के अवक्रमित होने का खतरा है, लेकिन विशेष दूत ने यह बात ध्यान दी है कि टुइमू हुआनकाओ (घास बढ़ाने के लिए जानवरों को हटाना) नीति के तहत चरवाहों को ऐसी स्थिति में नहीं लाना चाहिए कि वे अपने पशु बेच दें और कहीं और जा बसें।" विशेष दूत ने "चीनी अधिकारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि वे चरवाहा समुदाय के साथ सार्थक बातचीत करें,जिसमें पिछली एवं मौजूदा नीतियों के परिणामों का आकलन हो और ऐसे सभी विकल्प तलाशे जाएं जिससे घूमंतू चरवाहों की अपने इलाकों की जानकारी और आधुनिक विज्ञान से हासिल जानकारी का मेल किया जा सके।

सीमा क्षेत्र में चीनी गतिविधियां भारत के लिए खतराः निशंक

(पीटीआई, 24 दिसंबर)

नेपाल, पाकिस्तान और तिब्बत में चीनी गतिविधियों पर आशंका जताते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इस बात की संभावना है कि भारत के पड़ोस में चीनी प्रभाव बढ़ जाए, इसलिए भारत को तत्काल अपनी सीमा पर निगरानी बढ़ा देनी चाहिए। पोखरियाल ने कहा, "नेपाल, तिब्बत और पाकिस्तान में चीन की सक्रियता बढ़ रही है। हमें आशंका है कि इससे भारत–नेपाल सीमा पर भी भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जो भविष्य में हमारे देश के लिए खतरा बन सकता है।" जम्मू में गुरुवार को भाजपा के एक कार्यक्रम में पोखरियाल ने कहा," नेपाल में पाकिस्तान से आईएसआई की गतिविधियां बढ़ने को लेकर भी आशंका है।" उन्होंने कहा कि भारत के सीमावर्ती राज्यों की आंतरिक सुरक्षा सीधे तौर पर पड़ोसी देशों के हालात जैसे बाह्य कारकों से जुड़ी है।तिब्बत में बड़े पैमाने पर हो रहे सड़क निर्माण और चीनी लोगों के नेपाल में बसने को लेकर एक सवाल पर उन्होंने कहा," सीमा की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी एवं एसएसबी के जवान तैनात हैं, इसके बावजूद वहां कड़ी निगरानी शुरू करने की तत्काल जरूरत है।"उन्होंने कहा, "उत्तराखंड की सीमा नेपाल और चीन से मिलती है और नियंत्रण रेखा के साथ यह 350 किलोमीटर और करीब 250 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी गतिविधियां बढ़ने से राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है।"पोखरियाल ने बताया कि हाल में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आंतरिक सुरक्षा पर बुलाई गई एक बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने सुरक्षा के लिए दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया था।उन्होंने कहा,"प्रधानमंत्री के सामने पहली बात मैंने यह उठायी थी कि सीमा पर भारतीय इलाके में सड़कें बनाने की जरूरत है। चीन ने भारत–चीन सीमा पर तिब्बत में हिमालय की चोटियों तक सड़कों का जाल बिछा रखा है।"

चीनी सेना ने म्यांमार सीमा के नजदीक चौकी बनाई

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 29 दिसंबर)

अपने भारत दौरे के दौरान चीनी प्रधानमंत्री वेन च्यापाओ ने कहा था कि नई चीन–भारत साझेदारी विरोध और प्रतिस्पर्धा पर नहीं, बल्कि सहयोग पर आधारित है। इसके बावजूद

हालांकि यह राजमार्ग बनाने में चीन इस वजह से जल्दबाजी दिखा रहा है क्योंकि इसका सामरिक महत्व है। यह हिमालय के पूर्वी खंड में ब्रह्मपुत्र नदी की निचली धारा के पास अधिकृत तिब्बत की भारत से सटी सीमा के पास स्थित है।इसके दूसरी तरफ भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश है।

यही नहीं अगस्त, 2009 में दोनों देशों के बीच हुए सीमा वार्ता के 13वें दौर की रिपोर्टिंग के समय भी चाइना डेली ने भारत–चीन सीमा को 2000 किलोमीटर लंबा बताया था।

चीन द्वारा भारतीय सीमा के पास सैनिक ठिकानों का निर्माण जारी है। म्यांमार की मीडिया में 27 दिसंबर को छपी खबर के मुताबिक चीनी की जन मुक्ति सेना (पीएल) म्यामांर की सीमा के पास स्थित कस्बे में एक चार मंजिला सैन्य ठिकाना बना रही है जो भारत की उत्तर–पूर्व सीमा से भी नजदीक है।समाचार में कहा गया है कि अगस्त माह से ही सैन्य ठिकाने का निर्माण लगातार तेजी से जारी है और यह जल्दी ही पूरा हो जाएगा। इस ठिकाने में चीन के दक्षिण–पश्चिमी यून्नान प्रांत के सीमावर्ती कस्बे मेंघाई में बन रहे इस ठिकाने में कई सैन्य अधिकारी रहेंगे। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यह कम से कम एक पीएलए बटालियन के लिए कमान चौकी के रूप में काम करेगा।जिस इलाके में यह सैन्य केंद्र बन रहा है वह म्यांमार के उत्तरी शन राज्य के मोंगको कस्बे के सामने है और तिब्बत–म्यांमार–अरुणाचल त्रि संयोजन से सटा हुआ है। इससे सबसे नजदीक भारतीय इलाका वहाई है जो मिजोरम के पूर्वी छोर पर है।

चीन में भारतीय सीमा के नजदीक बन रहे राजमार्ग के लिए सुरंग निर्माण कार्य पूरा:

भारत काफी समय से इस बात का दबाव बना रहा है कि चीन अपने बाजार को और खोले, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है।

(टिबेटन रीव्यू)

चीन ने 15 दिसंबर को कहा है कि तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के निंगत्री प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित बोम काउंटी से मेतोक काउंटी को जाड़ने वाले सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 117 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के लिए एक बहुत ही जरूरी कार्य पूरा होने वाला है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिनहुआ के मुताबिक करीब 3,750 मीटर ऊंचाई पर बन रहे 3,310 मीटर लंबे गलोंगला पर्वत के सुरंग में सिर्फ तीन मीटर खुदाई का कार्य बचा है।चीन पिछले दो साल से इस सुरंग के निर्माण में लगा हुआ है। इसलिए जब 15 दिसंबर को सुबह 10 बजे दोनों तरफ के मजदूरों द्वारा 152 किलो विस्फोटकों के माध्यम से बचे हुए खंड में विस्फोट कराया गया तो यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। हालांकि राजमार्ग के निर्माण में अभी एक साल और लग सकते हैं।सुरंग के अंतिम छोर से तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के निगची प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित मेटोक काउंटी को जोड़ने वाले 90 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण अभी होना है।इस खंड के लिए निर्माण सामग्री सुरंग से होते हुए ही भेजी जा सकती है।

चीन का कहना है कि मेटोक काउंटी चीन जनवादी गणतंत्र की ऐसी अंतिम काउंटी है जिसमें कोई राजमार्ग नहीं है और इस परियोजना के पूरा होने के बाद इसका बाहरी दुनिया से अलगाव का इतिहास खत्म हो जाएगा। हालांकि यह राजमार्ग बनाने में चीन इस वजह से जल्दबाजी दिखा रहा है क्योंकि इसका सामरिक महत्व है। यह हिमालय के पूर्वी खंड में ब्रह्मपुत्र नदी की निचली धारा के पास अधिकृत तिब्बत की भारत से सटी सीमा के पास स्थित है।इसके दूसरी तरफ भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश है।

ब्रह्मपुत्र पर 24 नई परियोजनाएं बना रहा है चीन

(इंडियन एक्सप्रेस, 21 दिसंबर)

चीनी प्रधानमंत्री वेन च्यापाओ की भारत यात्रा संपन्न होने के कुछ दिनों बाद ही भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चला कि चीन में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों पर 24 नई परियोजनाएं(शायद जल विद्युत परियोजनाएं)बनाई जा रही हैं। गौरतलब है कि साल भर पहले राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान ने पता लगाया था कि ब्रह्मपुत्र पर चीन की तरफ सिर्फ ऐसे स्थान हैं जहां जल विद्युत परियोजनाएं

लाने की तैयारी की जा रही है।
खुफिया एजेंसियों को यह जानकारी मिली है कि जिन नई 24 परियोजनाओं पर काम हो रहा है वह जांगमू परियोजना के मुकाबले छोटी हैं। भारत ने ब्रह्मपुत्र पर चीन की तरफ बन रही जिन परियोजनाओं का पता लगाया है उनमें जांगमू अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। हालांकि, इसकी पुष्टि करने के साधन सीमित हैं, फिर भी भारतीय अधिकारी इस बात की सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि ये 24 नई परियोजनाएं स्थानीय जनता की जरूरतों को पूरा करने वाली छोटी नदी परियोजनाएं ही हों।

चीनी मीडिया ने भारतीय सीमा के बड़े हिस्से को भारत से अलग दिखाया
(हिंदुस्तान टाइम्स, 20 दिसंबर)
चीन–भारत सीमा को सिर्फ 2000 किलोमीटर लंबी (इसमें चीन के सीक्यांग और तिब्बत से सटी जम्मू–कश्मीर में स्थित 1600 किलोमीटर लंबी सीमा शामिल नहीं है) बताने वाली चीन की सरकारी मीडिया में छपी खबरों को लेकर भारत में बेचैनी है। भारत सरकार ने इन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और सूत्रों का कहना है कि चीनी मीडिया तो काफी समय से चीन–भारत सीमा को सिर्फ 2000किलोमीटर लंबी बताती रही है। चीन के विदेश मंत्रालय से जुड़े थिंक टैंक चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के उपाध्यक्ष रोंग यिंग ने कहा,"सीमा रेखा की लंबाई को लेकर हमेशा से विवाद रहा है।मीडिया में छपी खबरों में कुछ भी नया नहीं है।"भारत का लगातार यह कहना रहा है कि चीन के साथ उसकी सीमा 3,488 किलोमीटर लंबी है। चीनी प्रधानमंत्री वेन च्यापाओ की भारत यात्रा से पहले शिनहुआ ने खबर दी थी कि चीन–भारत सीमा 2000 किलोमीटर होने की जानकारी उसे चीन के उप विदेश मंत्री हु झेंगे के आधिकारिक बयान से मिली है। चीन के सरकारी अखबार द पीपुल्स डेली ने पिछले साल 7 जनवरी को लिखा था, "सीमा का मसला उपनिवेशवादी ब्रिटिश शासन के जमाने से चला आ रहा है। चीन और भारत करीब 2,000 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करते हैं और दोनों तरफ करीब 1,25,000 वर्ग किलोमीटर विवादित क्षेत्र है।" भारत–चीन रक्षा वार्ता की रिपोर्टिंग करते समय अखबार में इस तरह की खबरें छपी थीं। उसी दिन एक अन्य अखबार चाइना डेली ने भी कुछ इसी तरह की रिपोर्ट दी थी। यही नहीं अगस्त, 2009 में दोनों देशों के बीच हुए सीमा वार्ता के 13वें दौर की रिपोर्टिंग के समय भी चाइना डेली ने भारत–चीन सीमा को 2000 किलोमीटर लंबा बताया था।

चीन के भरोसा दिलाने के बावजूद उसके द्वारा ब्रह्पुत्र नदी पर बनाए जा रहे झांगमू बांध से भारत को होने वाले जल प्रवाह पर असर पड़ेगा

भारत ने एक चीन नीति को नजरअंदाज कर चीन को जवाब दिया

(टिबेटन रीव्यू डॉट नेट, 19 दिसंबर)
खबर है कि 15 से 17 दिसंबर तक की चीन के प्रधानमंत्री वेन च्यापाओ की भारत यात्रा के दौरान दो बार राजनयिक दृष्टि से ही सही, भारत ने चीन को जवाब देने की कोशिश की है। पहला मसला है क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था (आरटीए) और दूसरा है एक चीन नीति। इसके बदले चीन ने यह कोशिश की संयुक्त घोषणापत्र से मुंबई आतंकी हमला मामला और नत्थी वीजा मसले को बाहर रखा जाए।बताया जा रहा है कि आरटीए के मामले पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वेन से कहा है कि इसका अभी उपयुक्त समय नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच साल 2010 में होने वाले करीब 50 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार में भारी 'असंतुलन' है। हालांकि, इस दौरान दोनों देशों ने यह तय किया कि साल 2015 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक कर दिया

चुप्पी रखने और परमपावन दलाई लामा से दूरी बनाए रखने की हमारी नीति से चीनी हित तो सध रहे हैं, लेकिन हमारे भविष्य के हितों के लिए कोई फायदा नहीं हो रहा।

(1)

(2)

(10)

कैमरे की

1. धर्मशाला के मुख्य मंदिर सुगलांगखांग में 9 दिसंबर, 2010 को निर्वासित तिब्बती को संबोधित करते परमपावन दलाई लामा। इस अवसर पर तस्वीर में दिख रहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और विधानसभा अध्यक्ष श्री तुलसी राम।
2. परमश्रेष्ठ मिंड्रोलिंग खेनछेन रिनपोछे (दाएं) ने 4 दिसंबर, 2010 को भारत ज्योति
3. बाएं सेः इंडियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इलियट स्पर्लिंग, निर्वासित तिब्बती संस उच्चतर तिब्बती अध्ययन कॉलेज (सारा) की सुश्री सोनम ग्यालत्सेन, ब्रिटिश को (वाराणसी) के प्रोफेसर जाम्पा सामतेन और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन में शिक्षा विभ 'मंगोलिया एवं तिब्बत के बीच 1913 का समझौता' के उद्घाटन सत्र में। (फोटोः
4. चीन के लाउहे स्थित अपने घर में यू लिनडांग। लिनडांग को एक जमीन विवाद उन्होंने बताया कि उन्हें इस दौरान 54 बार बिजली के झटके दिए गए। (न्यूयॉ
5. जिग्मे ग्यात्सो। (टिबेट डॉट नेट)
6. तिब्बत में शुक्रवार, 14 मार्च, 2008 को आमदो लाबरांग के लाबरांग मठ के भिक्षु राष्ट्रीय झंडा हाथ में लिए प्रदर्शनकारी।
7. 1992 के दूतावास प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले 9 में से 8 तिब्बतियों को खाता (टीवाईसी)
8. शिमे ताशी की तस्वीर (साथ में नेपाल स्थित भारतीय राजदूत की मुहर भी दिख
9. सनग्रैब ग्यात्सो। फाइल फोटोः टीसीएचआरडी
10. ई. जेने स्मिथ ने विद्वानों को तिब्बती पुस्तकें उपलब्ध कराईं। (फोटोः ईवी एबेले)

(9)

(8)

(3)

(4)

की आंख से

तिब्बती संसद द्वारा हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सम्मान में आयोजित जलपान समारोह
ख रहे अन्य लोगों में बाएं से विपक्षी कांग्रेस की नेता विद्या स्टोक्स, राज्य के मुख्यमंत्री

ज्योति अवॉर्ड हासिल किया।
ो संसद के सदस्य श्री केलसांग ग्यात्सेन, आमने मछेन इंस्टीट्यूट के श्री ताशी सेरिंग,
श कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सेरिंग षाक्य, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय
ा विभाग में षोधार्थी श्री छुंग सेरिंग 30 दिसंबर, 2010 को धर्मशाला में आयोजित परिचर्चा
फोटोः टिबेट डॉट नेट)
विवाद के मामले में साढ़े छह साल तक दो मानसिक अस्पतालों में कैद रखा गया।
(न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए डू बिन)

भिक्षुओं के नेतृत्व में हुए एक व्यापक चीन विरोधी प्रदर्शन के दौरान प्रतिबंधित तिब्बती

ाता (परंपरागत तिब्बती शुभकामना का स्कॉर्फ) देकर सम्मानित किया गया। (फोटोः

दिख रही है)

एबेले)

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

(5)

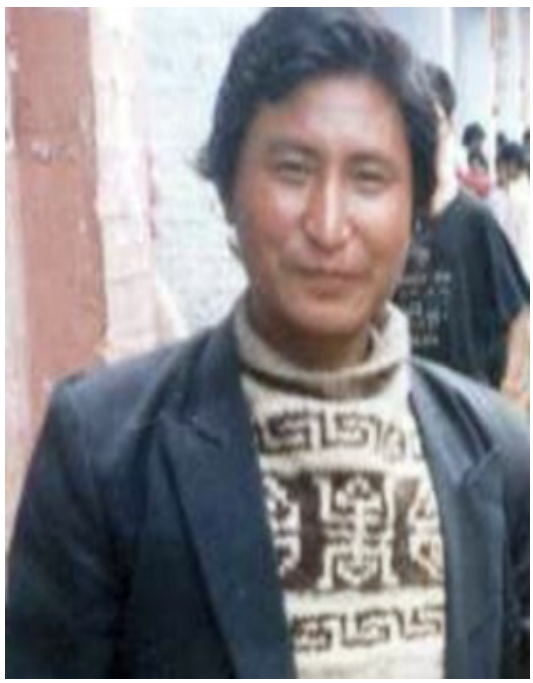

(7)

(6)

"आप यदि इतिहास को देखें तो चीन हमेशा से ही ज्यादा जमीन की अतृप्त भूख और दूसरों पर प्रभुत्व जमाने की उसकी महत्वाकांक्षा रही है। ये सब विश्वास और परस्पर भरोसे के आधार नहीं हो सकते।"उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया कि चीन का अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा को लेकर विवाद चल रहा है।

जाए। एक संवाददाता सम्मेलन में भारत की विदेश सचिव निरुपमा राव ने कहा, 'चीन के लोगों को यह जानना चाहिए कि हमारे द्विपक्षीय व्यापार में भारी असंतुलन है और हम दवा, कृषि उत्पाद एवं आईटी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में वहां के बाजार में और पहुंच चाहते हैं। कृपया इस संदेश को चीन तक पहुंचाएं।'गौरतलब है कि भारत –चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार अक्टूबर, 2010 तक बढ़कर 49.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, लेकिन इसमें चीन से भारत को होने वाले व्यापार 35 अरब डॉलर का है, जबकि भारत से चीन को होने वाला व्यापार करीब 15 अरब डॉलर का ही है। भारत काफी समय से इस बात का दबाव बना रहा है कि चीन अपने बाजार को और खोले, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ऑनलाइन ने 17 दिसंबर को उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से लिखा है कि भारत सरकार को संतुष्ट करने वाले कश्मीर की अखंडता जैसे शब्दों को यदि चीन नहीं दोहराता तो भारत संयुक्त घोषणापत्र में एक चीन नीति जैसे शब्दों को शामिल करने पर राजी नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि 'एक चीन नीति' जैसे शब्दों को 'परस्पर सम्मान एवं संवेदनशीलता' जैसे शब्दों को हटाकर लाया गया है जिससे यह पता चलता है कि इस समझौते से पहले खूब राजनयिक मोलतोल करने की जरूरत थी। भारतीय अधिकारियों के हवाले से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बातचीत के दौरान भारतीय पक्ष ने चीन को यह साफ संदेश दिया कि उन्हें 'कश्मीर को लेकर कई मसलों पर बात करनी है और चीन को इसे उसी संवदेनशीलता से देखना चाहिए जैसा कि वह तिब्बत और ताइवान के प्रति संवेदनशीलता रखता है और जिसका भारत पालन करने को राजी हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत और चीन द्वारा जारी संयुक्त घोषणापत्र से 'एक चीन नीति' जैसे शब्द बाहर हुए हैं। इन सबके बावजूद तथ्य यह है कि चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद और चीन–पाकिस्तान संबंधों को लेकर भारत असहज है जैसा कि रायर्टस की एक रिपोर्ट में बताया गया है।ऐसा नहीं लगता कि भारत सीमा के मामले में जारी मतभेद, चीन की कश्मीर नीति और भारत के प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से उसके गहरे रिश्तों के मसले को सुलझाने के करीब तक भी पहुंचा है।

तिब्बत पर भारत को ज्यादा साफगोई दिखानी होगी

(यूरेशिया रीव्यू, 6 दिसंबर)

बी. रमन

चीनी नेतृत्व ने तिब्बतियों के विद्रोह से सही सबक नहीं सीखा है। चीन को भरोसा है कि परमपावन दलाई लामा के निधन के बाद तिब्बत में थोड़ी–बहुत हिंसा होगी, लेकिन वहां की स्थिति को संभाल लिया जाएगा। तिब्बती स्कूलों में शिक्षा का माध्यम मंदारिन को बनाकर उसने तिब्बतियों की जातीय पहचान को नष्ट करने के कदम उठाए हैं।चीन सरकार के इस कार्य से वहां के युवाओं और शिक्षकों में विरोध की नई लहर शुरू हो गई है। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह तिब्बती युवाओं की उम्मीद को जिंदा रखे। तिब्बत में हो रहे इन घटनाक्रम पर भारत की पूर्ण चुप्पी से तिब्बती युवाओं का मनोबल कमजोर पड़ा है। चुप्पी रखने और परमपावन दलाई लामा से दूरी बनाए रखने की हमारी नीति से चीनी हित तो सध रहे हैं, लेकिन हमारे भविष्य के हितों के लिए कोई फायदा नहीं हो रहा। हमें तिब्बत के मामले में थोड़ी ज्यादा साफगोई दिखानी होगी।

कनाडा के अनुसंधानकर्ताओं ने कहा, चीनी बांध से होगा भारत को नुकसान

(असम ट्रिब्यून, 5 दिसंबर)

चीन के भरोसा दिलाने के बावजूद उसके द्वारा ब्रह्पुत्र नदी पर बनाए जा रहे झांगमू बांध से भारत को होने वाले जल प्रवाह पर असर पड़ेगा क्योंकि यह बांध तिब्बत में यारलंग सांगपो नदी के करीब आधी दूरी तक बना है। कनाडा के लेखक और फोटोग्राफर माइकल बकले ने यह खुलासा किया है। उन्होंने तिब्बत की गहन यात्रा की है और वहां के बांधों पर अनुसंधान के बाद एक फिल्म 'मेल्टडाउन इन टिबेट' बनाई है। ल्हासा से करीब 140 किलोमीटर दक्षिण–पूर्व के एक महाखड्ड में 3,260 मीटर ऊंचाई पर सांगपो नदी के बिल्कुल बीच में झांगमू बांध का निर्माण किया जा रहा है। झांगमू बांध से करीब 540 मेगावॉट बिजली उत्पादन होने का अनुमान है। बकले ने बताया कि बीजिंग सांगपो नदी पर अब तक का सबसे विशाल मोटुओ बांध भी बनाने की तैयारी कर रहा है जिससे करीब 38,000 मेगावॉट बिजली का उत्पादन होगा। यह बांध मेटोक क्षेत्र में स्थित होगा जो भूकंप संभावित क्षेत्र के करीब ही है। इस बांध की क्षमता अब तक बने तीन बड़े गॉर्ज बांधों की संयुक्त क्षमता से भी दोगुनी होगी। बकले ने कहा कि भारत और बांग्लादेश की ओर बहने वाली नदियों पर बांध के निर्माण से स्वाभाविक रूप से जल धाराएं मुड़ जाएंगी और इन नदियों के निचले हिस्से पर रहने वाले इन दोनों देशों को पानी कम मिलेगा। सौभाग्य से अभी चीनी इंजीनियरों ने कुछ समय के लिए मोटुओ बांध परियोजना को टाल दिया है। इस क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से अभी इस पर कोई काम नहीं हो पाया है। बकले ने कहा कि बारिश की वजह से वे बांध बनाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। चीन इस तरह से अंधाधुंध बांधों के निर्माण में लगा है कि जैसे उसे भविष्य की कोई चिंता नहीं है। फिलहाल चीन में 23,000 से ज्यादा बड़े बांध चालू हो चुके हैं।

भारत दक्षिण–पूर्व एशिया का सबसे स्थिर देशः दलाई लामा

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 12 दिसंबर)

दलाई लामा का कहना है कि भारत दक्षिण –पूर्व एशियाई क्षेत्र का 'सबसे स्थिर देश' है। लखनऊ में आयोजित दुनिया भर के मुख्य न्यायाधीशों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दलाई लामा ने यहां यह बात कही। दलाई लामा ने कहा, "चीन आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा आगे है, लेकिन भारत की स्थिरता उसकी स्वतंत्र न्यायपालिका, एक लोकतांत्रिक सरकार, किसी भी धार्मिक विश्वास को मानने की स्वतंत्रता और पारदर्शिता की वजह से है। भारत इन बुनियादी मूल्यों का फायदा उठा रहा है।" लखनऊ के सिटी मांटेसरी स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, दुनिया भर के मुख्य न्यायाधीश और भारतीय न्यायपालिका से जुड़े वरिष्ठ लोगों सहित करीब 1000 लोग शामिल हुए। दलाई लामा ने लोगों को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि 21वीं सदी को 'संवाद की सदी' के रूप में देखना चाहिए जहां हर चीज अफर्मेटिव एक्शन पर निर्भर हो। अपने को 'भारतीय विचार का संदेशवाहक' बताते हुए दलाई लामा ने अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और सौहार्द् पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "बौद्ध दर्शन के एक अनुयायी के नाते मैं धार्मिक सौहार्द् को बढ़ावा देने में विश्वास करता हूं। यह सब मैंने भारतीय परंपरा से सीखी है।"

भारत सरकार वास्तव में तिब्बतियों को पसंद नहीं करती तो उसे साफ तौर पर यह कहना चाहिए और उन्हें कहीं और भेज देना चाहिए। लेकिन यदि तिब्बतियों को यहां रखने का एकमात्र आधार मानवता है तो इसे भी साफ तौर पर दिखानी चाहिए।

चीन के सामने मजबूती से रखें अपना पक्ष

जापान ने इस महीने चीन की सैन्य तैयारी को 'अंतरराष्ट्रीय चिंता' बताया है। चीन ने इस महीने यह घोषणा भी की है कि वह अगले साल अपना खुद का विमान वाहक जहाज उतारने की तैयारी कर रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि चीन एक उभरते महाशक्ति के रूप में अपनी धमक बनाए रखने को प्रतिबद्ध है।

(इंडियन एक्सप्रेस, 16 दिसंबर) चीनी प्रधानमंत्री वेन च्यापाओ के तीन दिवसीय भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचने पर, राजधानी में दलाई लामा के प्रतिनिधि तेम्पा सेरिंग ने कहा है कि भारत को चीन के सामने मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए क्योंकि चीन सिर्फ 'ताकत को पहचानता है और मजबूत का ही सम्मान करता है।'

'भारत की चीन–तिब्बत नीति पर पुनर्विचार' विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सेरिंग ने सीमावर्ती इलाके में चीन द्वारा बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास पर सवाल उठाया और कहा कि तिब्बत क्षेत्र में हुई हाल की गतिविधियों पर भारत को ध्यान देना चाहिए। सेरिंग ने कहा, "आप यदि इतिहास को देखें तो चीन हमेशा से ही ज्यादा जमीन की अतृप्त भूख और दूसरों पर प्रभुत्व जमाने की उसकी महत्वाकांक्षा रही है। ये सब विश्वास और परस्पर भरोसे के आधार नहीं हो सकते।" उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया कि चीन का अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। उन्होंने तिब्बत में बुनियादी ढांचे के विकास की गति तेज करने को लेकर चीनी इरादे पर सवाल उठाया और कहा कि इनमें से ज्यादातर का लक्ष्य सैन्य ताकत को मजबूत करना है। सेरिंग ने बताया कि तिब्बत में कई मिसाइल बेस बनाए जा चुके हैं और रेलवे संपर्क को नेपाल एवं भारत में सिक्किम की सीमा तक बढ़ाया जा रहा है। इससे चीन के इरादे पर सवाल उठता है। उन्होंने कहा कि रेलवे संपर्क का इस्तेमाल तिब्बती इलाकों में हान चीनियों को बसाने में किया जा रहा है। उन्होंने बताया,"हर दिन तिब्बत के अंदर जाने वाली ट्रेनें करीब 4,000 चीनियों को लेकर जाती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2,000 ही वापस लौटते हैं। बाकी चीनी नागरिक तिब्बत में ही रुक जाते हैं, इससे तिब्बती जनसंख्या अल्पसंख्यक बनती जा रही है।" इस सेमिनार की अध्यक्षता मेजर जनरल (रिटार्यड) विनोद सहगल ने की। सेमिनार में शामिल अन्य वक्ताओं में सेंटर फॉर पॉलिसी आल्टर्नेटिव्स के डायरेक्टर मोहन गुरुस्वामी और सामाजिक कार्यकर्ता जया जेटली शामिल थीं।

बहुत पुरानी हैं चीन के मानवाधिकार उल्लंघन की जड़ें

(रेडियो फ्री एशिया, 17 दिसंबर) चीन पर प्रकाशित एक किताब को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है जिसमें इस बात की विस्तार से जानकारी दी गई है कि किस तरह से मानवाधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्षरण की घटनाएं चीन में शाही शासकों द्वारा 17वीं शताब्दी में शुरू हो गई थीं।'ड्रैगन ब्लड, वोल्फ स्मोक' नामक इस किताब में चीनी इतिहास के 256 ईसापूर्व में क्विंग साम्राज्य से लेकर 1912 में इस साम्राज्य के पतन तक का व्यापक विवरण पेश किया गया है। इस किताब में चीन के तानाशाही और क्रूर सरकारों के इतिहास को दर्शाया गया है जिनसे वहां की जनता पीड़ित थी और क्रूरता के इस इतिहास से वहां की राष्ट्रीय भावना को काफी नुकसान पहुंचा था। किताब में लेखक ने कहा है, "समकालीन चीन में अब कई लोग ऐसे हैं जो चीन को हान और तांग वंश के गौरवशाली दिनों की ओर लौटता देखना चाहते हैं। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि सचाई यह है कि इन वंशों का शासन रक्तरंजित रहा है और इनका तरीका निंदनीय रहा है।"हालांकि,ऑनलाइन पत्रिका बीजिंग स्प्रिंग के अमेरिका में रहने वाले संपादक हू पिंग का कहना है कि आज के मानवाधिकार कार्यकर्ता जिन सार्वभौमिक मूल्यों की बात करते हैं, वह चीन के लिए नई बात नहीं है। परंपरागत चीनी संस्कृति में भी काफी सौहार्द था और हमारे पूर्वज भी ऐसी चीजें चाहते थे।

भारत को चीन के प्रति ज्यादा सख्त रवैया दिखाना होगा

(पायोनियर, 29 दिसंबर)

सुनंदा के दत्ता रे

चोट पहुंचाने की इच्छा रखने लेकिन हमले से डरने के चीन के प्रति अपने रवैए से भारत दुनिया के सर्वोच्च मंच पर बैठने का मजबूत दावेदार नहीं हो सकता। एक राजभवन में हाल में एक भोज के दौरान एक ऐसी गलती का खुलासा हुआ है जिसे सिर्फ उत्सवी नहीं माना जा सकता। जब राज्यपाल ने दलाई लामा के साथ वहां प्रवेश किया तो हम सब जन–गण–मन के लिए सम्मान के साथ खड़े हो गए। इसके बाद मुझे उम्मीद थी कि तिब्बती राष्ट्रगान बजेगा, लेकिन अचरज की बात थी कि तिब्बती राष्ट्रगान नहीं बजाया गया। भारतीय राष्ट्रगान की समाप्ति के बाद सभी लोग परमपावन से मिलने के लिए लाइन में खड़े हो गए। प्रोटोकाल के इस गंभीर उल्लंघन से भ्रम की स्थिति बनती है जिसे उम्मीद की जाती है कि नए साल में दूर किया जाएगा। इससे एक असामान्य सोच का संकेत मिलता है और इस अक्षमता का भी कि भारत की राष्ट्रीय आकांक्षा को हासिल करने के लिए हम एक यथार्थ विदेश नीति को आकार दे सकते हैं। यह चलन वास्तव में कौतूहल पैदा करने वाला था क्योंकि नई दिल्ली के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे पहले यह बताया था कि दलाई लामा को किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जैसा दर्जा हासिल है। यदि ऐसा है तो मेजबान देश के राष्ट्रगान के तत्काल बाद उनका राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए था। नई दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में तो अन्य विदेशी मेहमानों के लिए राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर इसी परंपरा को निभाया जाता है। ऐसा हो सकता है (वैसे ऐसा लगता नहीं) कि तिब्बती प्रशासन का कोई राष्ट्रगान न हो,या ऐसा भी हो सकता है कि दलाई लामा ने खुद यह निर्णय लिया हो कि तिब्बती राष्ट्रगान न बजाया जाए ताकि भारत सरकार को असहज स्थिति में न आना पड़े। लेकिन यह दोनों बातें संभव नहीं लगतीं,क्योंकि दलाई लामा एक मानक पर चलने वाले व्यक्ति हैं। सच तो यह है कि तिब्बतियों के धर्मशाला प्रशासन ने राष्ट्र का दर्जा बनाए रखने के लिए हर साजोसामान तैयार किया है और वहां जल्दी ही एक नए प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। इससे भी बुरी बात यह है कि राजनयिक स्तर पर यह वायदा किया जाता है कि दलाई लामा को राजनीति नहीं करने दिया जाएगा और यह दावा किया जाता है कि वह निर्वासित सरकार नहीं चलाते। भारत सरकार वास्तव में तिब्बतियों को पसंद नहीं करती तो उसे साफ तौर पर यह कहना चाहिए और उन्हें कहीं और भेज देना चाहिए। लेकिन यदि तिब्बतियों को यहां रखने का एकमात्र आधार मानवता है तो इसे भी साफ तौर पर दिखानी चाहिए।

'तिब्बती आंदोलन को भारतीय जनता का सहानुभूति हासिल है', और 'भारत आमतौर पर निर्वासित तिब्बतियों और दलाई लामा के लिए सहयोगी घर रहा है।'

चीन हर दिशा में सैन्य संघर्ष की कर रहा तैयारी

(द टेलीग्राफ, 29 दिसंबर)

चीन 'हर दिशा में' लड़ाई की तैयारी कर रहा है। चीन के रक्षा मंत्री लियांग गुआंगली ने यह दावा किया है। चीन के कई सरकारी अखबारों में 29 दिसंबर को छपे लियांग के इंटरव्यू में यह बात सामने आई है। लियांग ने कहा,"अगले पांच साल में हमारी सेना हर सामरिक दिशा में सैन्य संघर्ष के लिए तैयारी को आगे बढ़ाएगी। हम शांतिपूर्ण समय में रह रहे हैं, लेकिन हम युद्ध को कभी नहीं भूल सकते, हम कभी भी अपने घोड़ों को दक्षिण नहीं भेज सकते या संगीनों

सीमा विवाद को हल करने के लिए भारत और चीन, दोनों को राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है।

मंगोलिया एवं तिब्बत, भाई–भाई जैसे हैं और एकसमान धर्म, संस्कृति एवं नस्ल से जुड़े हुए हैं।दिसंबर, 1911 में चीनी साम्राज्य के ढहने से मंगोल और तिब्बत ने बीजिंग के शासन रूपी बेड़ियों को तोड़कर फेंक दिया और दोनों ने अपने को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित किया।इसके बाद मंगोलिया एवं तिब्बत ने एक–दूसरे के बीच प्रतिरक्षा समझौता किया।

और बंदूकों को दूर नहीं कर सकते। चीन बार–बार यह कहता रहा है कि वह 'शांतिपूर्ण उभार' की योजना बना रहा है, लेकिन उसकी सेना का जिस गति और पैमाने पर आधुनिकीकरण किया जा रहा है उससे जापान सहित एशिया–प्रशांत के कई देशों में चिंता बढ़ गई है। जापान ने इस महीने चीन की सैन्य तैयारी को 'अंतरराष्ट्रीय चिंता' बताया है। चीन ने इस महीने यह घोषणा भी की है कि वह अगले साल अपना खुद का विमान वाहक जहाज उतारने की तैयारी कर रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि चीन एक उभरते महाशक्ति के रूप में अपनी धमक बनाए रखने को प्रतिबद्ध है।चीन एक कैरियर किलिंग बैलिस्टिक मिसाइल पर भी काम कर रहा है जो काफी दूरी से अमेरिकी विमान वाहक जहाजों को डुबा सकता है। जाहिर है चीन इस क्षेत्र में ताकत का संतुलन अपनी दिशा में करना चाहता है जिस पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका का प्रभुत्व है। लियांग ने कहा है कि चीन के आधुनि की करण के साथ ही उसके सशस्त्र बल ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीनी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि विशेषज्ञों के अनुसार अभी पश्चिमी तकनीक से पीछे है। लेकिन चीन तकनीक के मामले में आगे जाने का प्रयास कर रहा है। लियांग ने कहा, "चीनी सेना का आधुनिकीकरण दूसरों पर और खरीद पर निर्भर नहीं रह सकता। अगले पांच साल में हमारी अर्थव्यवस्था और समाज तेजी से विकसित होगा। हम इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी सेना के आधुनिकीकरण प्रयास को तेज करेंगे।"

दलाई लामा ने कहा, कालिमपोंग, दार्जिलिंग उनके दिल से जुड़ा है

(टिबेट डॉट नेट, 14 दिसंबर)

उत्तर–पूर्वी भारत के कालिमपोंग और दार्जिलिंग के साथ तिब्बत के पुराने रिश्ते को 'दिल के करीब' बताते हुए परमपावन दलाई लामा ने कहा कि बचपन में वह तिब्बती व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों से कालिमपांग, सिक्किम, दार्जिलिंग और कलकत्ता की यात्रा संस्मरण को सुनकर बहुत खुश होते थे। कालिमपांग के थार्पा छोलिंग मठ की 13 दिसंबर की यात्रा के दौरान दलाई लामा ने कहा,"उन दिनों मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कालिमपांग और दार्जिलिंग की यात्रा करूं।" यह मठ भारत के प्राचीनतम बौद्ध मठों में से एक है। दलाई लामा ने कहा, "इसके बाद 1956 में मुझे कालिमपांग और गांतोक की यात्रा करने का अवसर मिला। मैं भगवान बुद्ध के 2500 वीं जयंती के उत्सवों में शामिल होने के लिए आया था। साल 1959 में निर्वासन में आने के बाद तो भारत मेरा दूसरा घर बन गया।"

चीन–भारत सीमा विवाद का केंद्र बिंदु है तिब्बतः तिब्बती प्रधानमंत्री

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 15 दिसंबर)

चीनी प्रधानमंत्री वेन च्यापाओ की भारत यात्रा के दौरान निर्वासित तिब्बती प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत–चीन के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद से तिब्बत केंद्रीय रूप से जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर सामदोंग रिनपोछे ने कहा, "वास्तव में चीन–भारत सीमा विवाद नाम की कोई चीज नहीं है। दोनों देशों के बीच सीमा की समस्या में तिब्बत गुंथा हुआ है। सीमा विवाद को हल करने के लिए भारत और चीन, दोनों को राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। हालांकि, उन्होंने कहा कि चीन हमेशा इस मसले पर कठोर बना रहा है।उन्होंने कहा, 'जब तक तिब्बत का सवाल अधर में लटका रहेगा, इस क्षेत्र में स्थायी शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती।" पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के पश्चिमी हिस्से में चीन द्वारा सुरंग बनाने की खबर के बारे

में,जिसका इस्तेमाल चीन भारतीय शहरों को निशाना बनाने वाले मिसाइल तैनात करने में कर सकता है, उन्होंने कहा,"यह समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक भारी खतरा है।"उन्होंने कहा, यही नहीं चीन रेलवे लाइन के निर्माण का विस्तार नेपाल तक और सिक्किम की भारतीय सीमा तक कर रहा है, यह भी भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। प्रोफेसर रिनपोछे ने कहा, "हालांकि, निर्वासित तिब्बत सरकार यही चाहती है कि दोनों एशियाई दिग्गजों के बीच स्थिर संबंध हों। इससे इस समूचे क्षेत्र में स्थायी शांति आएगी।"

तिब्बतियों के प्रति सहानुभूति रखती है भारतीय जनता

(द हिंदू, 18 दिसंबर)

तिब्बत में मार्च, 2008 दंगों की शुरुआत के दो हफ्ते के बाद बाद दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास द्वारा भेजे गए एक संदेश में मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तत्कालीन विदेश सचिव शिवशंकर मेनन को अमेरिकी राजूदत से यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि 'तिब्बती आंदोलन को भारतीय जनता का सहानुभूति हासिल है', और 'भारत आमतौर पर निर्वासित तिब्बतियों और दलाई लामा के लिए सहयोगी घर रहा है।' हालांकि अधिकारियों ने यह भी स्वीकार किया था कि सरकार संतुलन बनाए रखने के कठिन चुनौती से गुजर रही है,क्योंकि नई दिल्ली से ओलंपिक मशाल गुजरने वाली है और इसका विरोध करने वालों पर कार्रवाई करने का चीन का दबाव बढ़ रहा है। यह केबल यानी संदेश विकीलीक्स द्वारा जारी नवीनतम दस्तावेजों का हिस्सा है। इससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका यह मानता है कि आखिरकार भारत सरकार भी उसी का समर्थन करेगी जिसको जनता का व्यापक समर्थन हासिल है।"

इस संदेश के एक और खंड में दलाई लामा के विशेष दूत लोदी ग्यारी अमेरिकी अधिकारियों को सुझाव देते हैं कि विरोध प्रदर्शनों के बाद भारत के बयानों पर 'सकारात्मक प्रतिक्रिया करें' क्योंकि 'भारत की विवशता को समझा जा सकता है और पहले के कोई बयान न जारी करने के चलन से यह तो बेहतर स्थिति है।'

दलाई लामा ने अपनी उपस्थिति से भारत को समृद्ध बनाया

(पायोनियर, 23 दिसंबर)

प्रेमेन एड्डी

भारत–चीन के खट्टे रिश्तों की जड़ में तिब्बत आता है।तिब्बत निर्विवाद रूप से 20वीं शताब्दी के पहले आधे हिस्से में काफी समय तक एक स्वशासी देश रहा है। माओवादी चीन ने 1950 में इस पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। यह भी तथ्य है कि भारत सहित पूरी दुनिया द्वारा तिब्बत पर चीन के शासन को वैधानिक मान लेने के बावजूद चीन कथित 'अलगाववादियों' के रोदन से मुक्त नहीं हुआ है जो उसके हिसाब से तिब्बत को 'मातृभूमि से अलग करने के लिए षडयंत्र रच रहे हैं। चीन चौदहवें दलाई लामा की भारत में उपस्थिति को लेकर गुस्से से खौलता रहता है, लेकिन वह इस बात पर जरा भी गौर नहीं करना चाहता कि आखिर वह भारत किन परिस्थितियों में आए। चीन के दमन से बचने के लिए दलाई लामा अप्रैल,1959 में भारत आए, जैसा कि उनके पूर्ववर्ती महान 13वें दलाई लामा ने फरवरी 1910 में किया था,जब चीनी सेनापति चाओ एर–फेंग ने ल्हासा में मार्च किया और वहां के बौद्ध मठों को लूटना शुरू किया। चीन यही चाहता है कि भारत सरकार दलाई लामा से यह कह दे कि वह किसी और देश जाकर रहें। लेकिन तथ्य यह है कि दलाई लामा ने अपनी उपस्थिति से भारत

इसका परिणाम तिब्बत और भारत को भुगतना पड़ा

विरोध प्रदर्शन में शामिल 70 साल के येशी छोजोन ने कहा, "भारत के लिए दीर्घकालिक हित इसी बात में है कि तिब्बत को एक बफर जोन बनाया जाए। जब तक ऐसा नहीं होता है, भारत पर चीन सैन्य, राजनीतिक और पर्यावरणीय दबाव बनाता रहेगा।"

को समृद्ध किया है,यदि परमपावन को दबाव में यहां से जाना पड़ता है तो यह भारत के लिए अवज्ञा करने जैसा होगा और भारतीय लोग इससे शर्मिंदगी महसूस करेंगे।

इससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका यह मानता है कि आखिरकार भारत सरकार भी उसी का समर्थन करेगी जिसको जनता का व्यापक समर्थन हासिल है।"

एफई के मंगोलिया का हवाला देने से क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय सामने आया है। मंगोलिया एवं तिब्बत, भाई–भाई जैसे हैं और एकसमान धर्म, संस्कृति एवं नस्ल से जुड़े हुए हैं। दिसंबर, 1911 में चीनी साम्राज्य के ढहने से मंगोल और तिब्बत ने बीजिंग के शासन रूपी बेड़ियों को तोड़कर फेंक दिया और दोनों ने अपने को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित किया।इसके बाद मंगोलिया एवं तिब्बत ने एक–दूसरे के बीच प्रतिरक्षा समझौता किया। आज भी मंगोलिया एक संप्रभु देश है जिसको पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय स्वीकार करता है। भारत में शासन के दौरान अंग्रेजों ने तिब्बत के प्रति कम दृढ़ और ज्यादा कुटिल रवैया अपनाया और तिब्बत की संप्रभुता एवं अधिकार क्षेत्र के बारे में तमाम कुतर्क देते रहे जो कि जुलाई 1914 में हुए शिमला समझौते का भी हिस्सा रहा। इसका परिणाम तिब्बत और भारत को भुगतना पड़ा, हालांकि यह भारत के मुकाबले तिब्बत के लिए ज्यादा कष्टदायी रहा।

वेन च्यापाओ की भारत यात्रा का तिब्बतियों ने किया विरोध

(आईएएनएस, 17 दिसंबर)

'जब तक तिब्बत का सवाल अधर में लटका रहेगा, इस क्षेत्र में स्थायी शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती।"

चीन के प्रधानमंत्री वेन च्यापाओ की तीन दिवसीय भारत यात्रा के विरोध सैकड़ों तिब्बतियों द्वारा दिल्ली के जंतर–मंतर पर किया जा रहा विरोध प्रदर्शन 17 दिसंबर को समाप्त हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि 'तिब्बत की आज़ादी' के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन में शामिल एक तिब्बती छात्र तेनजिन लामो ने कहा, "हमारी लंबे समय से एक ही मांग रही है। तिब्बत को आज़ाद करो। वहां हो रहे मानवाधिकार के घोर उल्लंघन को बंद करो। च्यापाओ की यात्रा संपन्न होने के साथ ही तीन दिन से चल रहा यह विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है,लेकिन आज़ादी के लिए हमारी लंबे समय से चल रही लड़ाई जारी रहेगी।" वेन की यात्रा की शुरुआत के समय से ही तिब्बती समुदाय जंतर–मंतर पर धरने पर बैठा था। इस दौरान 16 दिसंबर को दो अलग घटनाओं में पुलिस ने वेन की यात्रा का विरोध कर रहे 30 तिब्बतियों को गिरफ्तार कर लिया।विरोध प्रदर्शन में शामिल 70 साल के येशी छोजोन ने कहा ,"भारत के लिए दीर्घकालिक हित इसी बात में है कि तिब्बत को एक बफर जोन बनाया जाए। जब तक ऐसा नहीं होता है, भारत पर चीन सैन्य, राजनीतिक और पर्यावरणीय दबाव बनाता रहेगा।"

तिब्बती आध्यात्मिक नेता को भारत ज्योति अवार्ड

(टिबेट डॉट नेट, 17 दिसंबर)

मिंड्रोलिंग वंश के दूसरे सर्वोच्च आध्यात्मिक प्रमुख परमश्रेष्ठ मिंड्रोलिंग खेनछेन रिनपोछे को नई दिल्ली में 4 दिसंबर को भारत ज्योति अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।इस युवा अवस्था में भी विभिन्न देशों में बेहतरीन सेवा, बेहतरीन प्रदर्शन और उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए खेनछेन रिनपोछे को यह सम्मान दिया गया है। वह उत्तर भारत के देहरादून स्थित मिंड्रोलिंग गाग्यूर निमा कॉलेज के प्रमुख हैं। यह सम्मान उन असाधारण पुरुषों या महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, उद्योग, ललित कला, राजनीति और सामाजिक कार्यों में बेहतरीन सेवा की हो। दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय मैत्री समाज द्वारा आयोजित "भारत के आर्थिक विकास में अंतरराष्ट्रीय भागीदारी" विषय पर आयोजित सम्मेलन के दौरान ही इस पुरस्कार समारोह का भी आयोजन किया गया।